

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के फुंडरी में निर्माणधीन उच्च स्तरीय पुल का किया निरीक्षण

पायनियर संवाददाता ✍ बीजापुर

www.dailypioneer.com

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के एक दिवारीय प्रवास के द्वारा भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम फुंडरी में इंद्रांशी नदी पर निर्माणधीन उच्च स्तरीय पुल का स्थल निरीक्षण किया। इस पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, किंतु अभी ये पिलर का कार्य शेष है। निरीक्षण के द्वारा उपमुख्यमंत्री ने निर्माण ऐसी और संबंधित विधायी अधिकारियों से अब तक की प्राप्ति, निर्माण में हुई रेतों के कारणों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि कार्य में विलंब अब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उहोंने कहा कि यह पुल बीजापुर और नारायणपुर जिले के बीच आवागमन का एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु बनेगा और इसके पूर्ण होने से बेत्र के लाखों लोगों के जीवन में पर्यावरण आएगा। उहोंने पुल निर्माण कार्य को जनसेवा से जुड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर इसे एक निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता-वृक्ष पूर्ण किया जाना चाहिए।



फुंडरी पुल-विकास का प्रवेश द्वार : उपमुख्यमंत्री शर्मा

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह पुल केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि बीजापुर और नारायणपुर जिले के हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। इस पुल का माध्यम से जहाँ आवागमन की सुविधा सुलभ होगी, वहीं शासन की विभिन्न जनकल्पनाओं योजनाएं जैसे रोशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एवं सामाजिक सुरक्षा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक तेजी से पहुँच पाएंगी। उहोंने बाताया कि पुल के बन जाने से बीजापुर और नारायणपुर के मध्य की दूरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे बीजापुर के ग्राम पंचायत बागली, बैल, तालिलोड, मर्मटेड, इतामपारा सहित नारायणपुर के गांव डुंगा, थुथली, रेखाबाया,

समर्पण से होगा निर्माण संभव समयसीमा होगी अनिवार्य

उपमुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में समर्पण, तकनीकी दक्षता और सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। उहोंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये पुल निर्माण की साझाहिक समीक्षा करें, विभिन्न समीक्षाएँ की जांच सुनिश्चित करें और कार्य स्थल पर श्रमिकों एवं तकनीकी अधिकारियों की उपस्थिति बनाएं। उहोंने यह भी निरीक्षण किया कि यदि ठेकेबार या प्रजार्थी निर्माण कार्य को समयसीमा में पूर्ण करने में अक्षम पाई जाती है तो ऐश्वरिक कार्यार्थी सुनिश्चित की जाए निरीक्षण के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ श्रीमंति बीम सिंह, बस्तर रेज के पुलिस महानियोंक शुंदरराज पी., शीआड़जी कमलोलेख कर शृंग, बीजापुर कलेक्टर सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, कमलांगाड़ी कर्मी रंगानाथ रामवल्लभ वाया, जिला पंचायत सीईओ एवं पुलिस विभाग के विष्ट अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास का रोडमैप तैयार, सरकार प्रतिबद्ध

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह पुल केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि बीजापुर और नारायणपुर जिले के हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। इस पुल का माध्यम से जहाँ आवागमन की सुविधा सुलभ होगी, वहीं शासन की विभिन्न जनकल्पनाओं योजनाएं जैसे रोशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एवं सामाजिक सुरक्षा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक तेजी से पहुँच पाएंगी। उहोंने बाताया कि पुल के बन जाने से बीजापुर और नारायणपुर के मध्य की दूरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे बीजापुर के ग्राम पंचायत बागली, बैल, तालिलोड, मर्मटेड, इतामपारा सहित नारायणपुर के गांव डुंगा, थुथली, रेखाबाया,

निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उहोंने संबंधित इंजीनियरों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया और कहा कि नवीनिर्मित भवनों में छत से पानी टपकने या दरार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बैठक में अधिकारी विकास विभाग द्वारा संचालित विभाग के प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आश्रम और आग्रावास की स्थिति एवं छत्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि आश्रम व छत्रावासों में बच्चों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराएं, जिससे वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उहोंने बच्चों के मानविक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय-समय पर कार्यसिलिंग की बात आयुक्त, अधिकारी विकास समय-समय पर रखने में खालीपाणी व बिप्रवान अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक ली

पायनियर संवाददाता ✍ कोणडांगा

www.dailypioneer.com

कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उहोंने आगंबाड़ी कंदों की स्वच्छता और समुचित खरबाखाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं का समय पर एनसीपी एवं नियमित जांच करने पर जोर देते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु के बेडरूम स्वास्थ्य के लिए समयबद्ध जांच बहुत आवश्यक है। कलेक्टर ने सुकूप समस्त योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगंबाड़ी कार्यकर्ताओं को बलिकाओं के अधिभावकों को योजना की जानकारी देकर खाता खोलने के लिए प्रेरणा करने के

निर्देश दिए। उहोंने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अधिकार के अंतर्गत बालिकाओं की सुकूप और समर्थनकारी योजनाएं जैसे रोशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एवं सामाजिक सुरक्षा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक तेजी से पहुँच पाएंगी। उहोंने कहा कि विद्यालय छोड़ चुकी बलिकाओं की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश भी दिया। बैठक में विभायी निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अधिकार के अंतर्गत बालिकाओं को महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु जनजागरूकता बढ़ाने को कहा। उहोंने कहा कि विद्यालय छोड़ चुकी बलिकाओं की काउंसिलिंग कर उठाए जाने के लिए जांच दें। उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग की समीक्षा की जाने का उद्देश्य निर्माण कार्यों की भी निर्देश दिया।

उहोंने बाल विकास विभाग

नियम विरुद्ध जमीन की बिक्री, आक्रोशित आदिवासी समाज पहुंचा कलेक्टरेट

कलेक्टर ने दिया जांच का आशासन, भूमाफियाओं में हड़कंप

पायनियर संवादकाता ▲ धर्मती
www.dailypioneer.com

छग भू-राजस्व संहिता अधिनियम के नियमों को बताये ताक रखकर जिले के तकालीन कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों ने आदिवासी समाज के सदस्यों की खुफियों को बिक्री किये जाने की अनुमति देने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जिसके चलते अब समाज ऐसे लोगों के समर्थन में लाभदात हो चका है और उन्होंने पिछले दिनों कलेक्टर अविनाश मिश्र को इस संबंध में एक जापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी जांच की मांग की है। समाज की भावनाओं को और उनकी शिकायतों को लेकर पायनियर ने लगातार इस संबंध में शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है जिसका असर यह रहा कि इस खबर को प्रशासन ने भी जूँझना में लिया है और नियम विरुद्ध जमीन

पायनियर
खबर का असर



जमीन दलालों को अपनी भूमि विक्रय किया है, वे अब अधिकारीयों को भूमियों को विक्रय किये जाने की अनुमति के पीछे चल रहे रेक्टर का परदा फाश किया है। इन्होंने तकालीन अधिकारियों पर अरोप लगाया है कि वे छग भू-राजस्व अधिकारियों ने ऐसे ऐसे आदेश किये हैं जिसके तहत एक व्यक्ति का नाम चेतन नाम है। लेकिन खरीदार का नाम शासन बताया गया है। यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया था जहां सूचना के अधिकार के तहत दूसरा ही नाम खरीदार में बताया गया है। इसी तरह तकालीन

अधिकारी, पटवारियों ने मिलकर भूले भाले आदिवासी समाज के सदस्यों को पूर्व जो विक्रय करने की अनुमति के पूर्व जो विक्रय होती है, उसमें भी उहोंने घालमेल किया है। इन्होंने स्थल निरीक्षण किये बिना और यह जानकारी लिये बिना कि उक्त सदस्य के खते में कितनी भूमि आयेगी, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। जिला आदिवासी समाज की ओर से सौंपे गये जापन में वैसे तो अनेक अरोप अधिकारियों पर लगाये गये हैं। इनमें से कुछ लोगों ने

पॉयनियर संवाददाता को भी अपनी पीड़ा बताते हुए आदिवासी समाज के सदस्यों की भूमि को खरीदी बिक्री किये जाने पर नाराजगी जताई थी। उहोंने यह भी बताया था कि छग भू-राजस्व संहिता के तहत जो कार्यवाही होती चाहिये थी, जांच पड़ताल होनी चाहिये थी, उसका पालन नहीं किया गया है। इस कारण आदिवासी समाज के सदस्यों के पास कम भूमि बची है जिससे उनके परिवारों का जीवन यापन नहीं हो रहा है। इस जानकारी को पॉयनियर ने लगातार

प्रकाशित कर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने की दशा में उक्त समाज उद्देशित हो गया और उसने पिछले दिनों कलेक्टर के एक शिकायत देकर तकालीन अधिकारियों, पटवारियों पर गंभीर अरोप लगाते हुए आदिवासी समाज के सदस्यों की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं दिये जाने की मांग की है। साथ ही उहोंने यह भी कहा है कि इकारनामा करने के बाद उक्त लालू शुल्क होता है कि इकारनामा करने के बाद उक्त आदिवासी समाज के सदस्यों को गैर आवेदन देने के लिये बाध्य किया जाता है और वह आवेदन कलेक्टर के कार्यालय में प्रस्तुत करता है जहां से जांच एसडीएम के माध्यम से तहलीदार, पटवारी को धारण करने के पश्चात 5 एकड़ भूमि सिवित है, उनसे उक्त भूमियों को बापस दिलाया जाये। अन्यथा ऐसा न होने की दशा में समाज के लोग चयनबद्ध तरीके से शारीरिक धरान प्रदस्त करने के पश्चात 5 एकड़ भूमि सिवित है, कि नहीं किंतु बैठकर ही उपर्याप्त धूक रुक्मि, गोविन्द रावट, चंद्रकला नेताम, ईश्वरी नेताम, जयपाल ठक्कर, ठक्कर, राम नेताम, नेमसिंह नेताम, नारायण धूक, खिलौंद्र पडोटी, दरिशकर मरकाम, दिविजय सिंह धूक, युवराज मरकाम, हेमत धूक समेत समाज के अनेक लोगों के नाम शामिल हैं।

मॉक पार्लियामेंट में जानकी गुप्ता को मिला प्रशिक्षित पत्र

पायनियर संवाददाता ▲ धर्मती
www.dailypioneer.com

डॉ ममता साहू कार्यक्रम प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों के नेतृत्व में 30 जून 2025 स्थान अग्रसेन कालेज यूनिवर्सिटी राज्यपूर्वक राज्यीय संगठन के द्वारा निर्देशित मॉक संसद का आयोजन किया गया जिसमें सुख्त बक्का डॉ सरोज घाटे पार्टी राजीव उपाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, अध्यक्षता किण्णु किया गया रही ताक राज्यव्यवस्था पर अधिकारियों ने ऐसे ऐसे आदेश किये हैं जिसके तहत एक व्यक्ति का नाम चेतन नाम है। लेकिन खरीदार का नाम शासन बताया गया है। यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया था जहां सूचना के अधिकार के तहत दूसरा ही नाम खरीदार में बताया गया है। इसी तरह तकालीन



सभा को संबोधित किया। अतिथियों के द्वारा प्रस्तुत पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम प्रभारी ममता साहू के नेतृत्व में लगभग 35

प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्ता पक्ष से 22 प्रतिभागी थे, जिनमें के 9 प्रतिभागी थे। एक लोकसभा अध्यक्ष, दो मार्शल, 2 साहायक थे। पक्ष और विषयक द्वारा आपातकाल के विषय पर प्रकाश ढाला गया। जानकी गुप्ता ने बताया कि युवाओं में अनुरूप जोश और नेतृत्व क्षमता दिखाई दी। सभी के अंदर देस के लिए कुछ करने का जज्जा था। युवाओं में देश के प्रति समर्पण की भावना देखते ही बन रही थी। पक्ष और विषय दोनों को अपने विचार रखने का मौका दिया गया। बाद विवाद देखने लायक था जिससे युवाओं में नेतृत्व के साथ तक्षशीलता को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित करने और प्रशिक्षित पत्र प्रदान करने के लिए जानकी गुप्ता ने आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक



पायनियर संवाददाता ▲ बलोदाबाजार
www.dailypioneer.com

मतदान सूची में नाम जोड़ने, काटने, विलोपन करने स्थानांतरण करने संबंधी प्राप्त 06, 07, 08 की प्रति भी प्रदान की गई साथ ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तथा नया मतदान केन्द्र, स्थल, भवन परिवर्तन, अनुभाग परिवर्तन आदि के संबंध में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि भारत निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को संधारित करने एवं मतदान केन्द्रों के विस्तृत करने के लिए निवाचन आयोग एवं मुख्य निवाचन पार्थिवकारी रायपुर के निर्देशनामान्तर मतदान केन्द्रों का



छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के
नए अवसर

“अब उद्यमी बनने की
राह हुई आसान



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सिंगल विंडो सिस्टम 2.0

- 👤 पोर्टल के माध्यम से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा
- 🏭 उद्योगों की स्थापना में सहयोग, युवाओं को टोजगार के मौके
- 🌐 ऑफलाइन मोड में किसी भी कायलिय जाने की आवश्यकता नहीं
- ₹ पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का कलीयरेंस
- 👉 ई-चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा
- 👉 सिंगल क्लिक पर देखी जा सकती है आवेदन की स्थिति

Samvad-44435/1



सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [f](#) [x](#) [@](#) [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क